

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,
अपर सचिव एवं अपर विधि महामंत्री
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

श्री पीठ एन० गुप्ता,
अधिवक्ता,
कक्ष संख्या 55, लायसे चेंबर,
नई दिल्ली ।

भाषा अनुभाग - 1

देहरादून दिनांक 24 मई, 2007

विषय- माननीय उच्चतम न्यायालय में उत्तराखण्ड राज्य की ओर से पैरवी/वहस किया जाने हेतु एकीकृत ऑन रिकार्ड के रूप में आवद्ध किया जाना ।

महोदय,

आपका विषयक मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन ने समयक विनाशेषकत्वा माननीय उच्चतम न्यायालय में उत्तराखण्ड राज्य का पक्ष प्रस्तुत करने के लिये आपको एकीकृत ऑन रिकार्ड में रज में शासनादेश जारी होने की तिथि से अग्रिम आदेशों तक आवद्ध किया जाने का निर्णय लिया है ।

3. तबत आवद्धता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यह किसी भी समय बिना किसी पूरे सूचना के समाप्त की जा सकती है ।

4. आपको उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-128-एक(6)/छापीरा(1)/न्यायक अनु० /2005 दिनांक 12-9-2005 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्धारित फीस अनुमन्य होगी ।

5. मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि यदि सम्भव हो तो कृपया अपनी लिखित सहगी उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें ।

भवदीय

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव

संख्या 255/XXXV(1)/2007-15जी/2000 तदुदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1- महासचिव, उत्तराखण्ड, मजरा, देहरादून ।
- 2- महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, गैनीताल ।
- 3- महाराजिव, मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
- 4- महानियन्त्रक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, गैनीताल ।
- 5- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
- 6- अपर मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन ।
- 7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
- 8- विशेष कार्यधिकारी मुख्यमंत्री को मा० मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ ।
- 9- श्री रचना श्रीवास्तव, अपर महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड शासन 39 न्यू लायसे चेंबर, भागवत दास रोड नई दिल्ली ।
- 10- इरला पैक अनुभाग/गाइड फाइल N.I.-C

आज्ञा से

(एम० एम० रोषवाती)
अनु सचिव ।